Impact Factor (SJIF): 6.126 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 26/August/2025 IJRAW: 2025; 4(10):43-45 Accepted: 06/October/2025

नक्सलवाद भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या एवम् उसका समाधान

*[1]ऋषि कुमारी

*[1]शोधार्थी, रक्षा एवं स्नातजिक अध्ययन विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत देशवासियों के प्रयत्नों एवं महान व्यक्तियों के नेतृत्व के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतन्त्रता तो मिली, लेकिन स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश कूटनीति के कारण कुछ ऐसी सुरक्षात्मक समस्याएं रह गई जो आज भी विद्यमान है, जैसे- हिंसात्मक अराजकता, विघटनकारी तत्य, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, माओवादी हिंसा नक्सलवाद, आतंकवाद आदि। इन सभी समस्याओं में नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसके कारण देश की आंतरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता भी प्रभावित हो रही है।

नक्सलवाद एक विचारधारा है और इस विचार धारा को मानने वाले अब लोकतंत्र पर हमला करने में लगे हैं जिससे भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। नक्सलवाद का उद्देश्य शासन के विरुद्ध जनयुद्ध की परिकल्पना थी आज इसका अर्थ सिर्फ चंदा उगाही और पुलिसबलों पर हमला करके हथियार लूटना है। नक्सली चाहते हैं कि आदिवासी इन्ही मंसूबो को स्थानीय आदिवासी समझने लगे हैं।

नक्सलवाद के समाधान के रूप में सर्वप्रथम नक्सलवाद के प्रचार प्रसार को रोकने तथा राज्य सरकारों को क्षेत्र में विकास की रणनीति के तहत शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधायें देनी वाहिए। साथ ही सफेदपोश समर्थकों शहरी नेटवर्क तथा स्थानीय मददगारों पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है।

मुख्य शब्दः नक्सलवाद का प्रारम्भ व विकास, नक्सलवाद के पनपने व जारी रहने के कारण भारत में नक्सलियों द्वारा किये गये प्रमुख हिंसात्मक घटनायें, नक्सलवाद रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाये गे प्रमुख अभियान आदि।

प्रस्तावना

नक्सलवाद का प्रारंभ व विकास

'सत्ता बन्दूक की नली से निकलती है' माओत्से युग की इसी विचार धारा से प्रेरित होकर चारू मजूमदार कानू सान्याल, जंगल संथाल ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले नक्सलबादी गावें में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरूआत की, इसलिए इसे नक्सलवाद कहा गया।' नक्सलवाद का आशय है माओं के क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद जिसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। नक्सलवादियों ने लोकतात्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जनक्रांति पर बल दिया है।

इस आन्दोलन के नेता चारू मजूमदार का अनुमान था कि "भारत का हर कोना एक ज्वालामुखी बन चुका है। यह फूटने वाला ही था और भारत में बहुत ज्यादा उथल पुथल की सम्भावना थी। यह ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सदस्यों का आह्वान किया। उनका सदेश था संघर्ष कही भी और हर जगह विस्तार करो कालान्तर में उसने छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा में भी आधार निर्माण का कार्य किया।"

वर्तमान में नक्सल गतिविधियां देश के 20 राज्यों के 223 जिलों में 2000 थाना क्षेत्रों में फैली हुई हैं। जिनमे प्रमुख राज्य हैं-पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश झारखण्ड, बिहार उड़ीसा, छत्तीसगढ, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश। देश के लगभग छठवे हिस्से पर नक्सली अपना मजबूत नियंत्रण जमा चुके हैं। नक्सली समस्या मूलतः सामाजिक, आर्थिक विकास और शोषण उत्पीड़न से जुड़ी हुई है, इसलिए बन्दूक और सैनिकों के बल पर इसका समाधान संभव न होगा। इसके लिए एक बडा वरग विकास से वंचित, शोषित व प्रताड़ित है जबकि यह विकास दर को दहाई के आंकड़े पर लाने की बात की जा रही है लेकिन इसका फायदा गरीब व वंचित तबके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार की एक समस्या है। इसकी जड़े अन्याय बोध की भावना से जुड़ी है। नक्सली समस्या के पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताएँ छिपी है। अब तक केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था को कानून-व्यवस्था का मामला मानकर हल करने की कोशिश की है। यही कारण है कि आज लगभग चार दशकों के बाद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है।'

नक्सलवाद के पनपर्ने व जारी रहने के कारण-

i). नक्सलवाद की उत्पत्ती का मूल कारण पिछड़ापन है जिससे अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ रही है तथा भू-स्वामियों व मजदूरों के बीच आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है।

*Corresponding Author: ऋषि कुमारी

ii). प्रचलित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का पतन, आय-विषमता, जातीय तनाव तथा बढ़ती आबादी।
iii). शोषण की पराकाष्ठाए जिसमें विस्थापन व जबरदस्ती बे दखली शामिल है।
iv). पिछड़े वर्ग व आदिवासियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया क्योकि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से पिछड़े क्षेत्रों के लिए आने वाली राशि उन तक नहीं पहुँच पाती। योजना आयोग के तहत सरकार जो खर्च करती है, उसमें एक रूपये का केवल 16 पैसा ही गरीब जनता तक पहुँचता है।'
v). बढ़ती बेरोजगारी जिसके कारण निरूद्देश्य युवा नक्सली आन्दोलन से आसानी से जुड़ जाते हैं क्योकि रोजगार के कोई अन्य साधन न हो पाने के कारण वे इसे आय का जरिया बना लेते
vi). मौलिक सुविधाओं सम्बधी अभाव जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, आवास सम्बंधी समस्याएं, अस्पताल, बिजली आदि का अभाव है। जिसके कारण स्थानीय नागरिकों ने सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है।
vii). मानवाधिकारों व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही संभव न हो पाना।
viii). नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण नक्सली उन्हे बहला फुसलाकर अपने में मिला लेते है। तथा एक ऐसी शिक्षा का अभाव जो लोगों में देश की भावना जागष्त करने के साथ-साथ लोगो को स्वरोजगार के लिए भी तैयार करे।
ix). न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था सही समय पर न्याय देने में असफल होने के कारण भी नक्सली समस्या बढ़ती जा रही है।
x). नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों पर प्रतिबंध ना लगना।
xi). लोकतांत्रिक खुलेपन के कारण धन और हथियारों का आसानी से विदेशों से प्रवेश।"
xii). मतदान राजनीति की विकर्षत और स्थानीय शासन संस्थानों का असंतोषजनक ढंग से कामकाज करना।
xiii). पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग और कानूनी मानदण्डों के उल्लंघन करना।

अगर भारत में माओवादी और नक्सलवादी आन्दोलन बढ़ गया तो चीन बड़े पैमाने पर प्रशासनिक डोंचे को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूरण तथा संवेदनशील बनाया जाये ताकि आम नागरिक इस पर विश्वास कर सके।"

बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम एवं राष्ट्रीय रोजगार कानून को नक्सल प्रभावित जिलों में प्राथमिकता से लागू किया जाए। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए विशेष प्रयात्त किए जाने चाहिए क्योकि नक्सलियों के पास न केवल आधुनिक हथियारों का जखीरा है बल्कि उनकी संरचना एवं सूचना प्रणाली भी आधुनिकतम यंत्रों से लैस हो चुकी हैं पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के भी कारगर समन्वय बनाना चाहिए। केन्द्र सरकार को पहल करते हुए एक समन्धित एवं एकरूप कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए।"

केन्द्र सरकार को सुरक्षा व विकास के दोनों मोर्चा पर प्रभावित राज्यों के प्रयासो में सहयोग कराना जानी रखना होगा। भूमि सुधारों के त्वरित कार्यान्वियन के एक भाग के रूप में भूमिहीन निर्धन लोगों की भूमि वितरित करने, आदिवासियों की जल, जंगीन समस्या का सनाधान करने और सडक, संचार, विद्युत जैसी भौतिक अवस्थापना का विकास सुनिश्यित करने, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा आम लोगों की स्थानीय समस्याओं तथा उनके असंतोष को खत्म करने के लिए नीतियों का सही कार्यान्वयन अति आवश्यक है। सरकारी नीतियों को लागू करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकारी तंत्र उनको सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं सरकार को नक्सलियों को समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।

नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है यह मूलतः एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार एवं समाज को एक बहुआयामी रणनीति बनानी चाहिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित व सुदष्ढ करने के लिए आवश्यक है कि हमारा ढाँचा सुसंगठित राष्ट्रीय हित व राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हो। आंतरिक सुरक्षाओं का निदान केवल सेना या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है अपितु हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि वह राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें और ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न न करे ताकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई विद्रोही ताकत बाड्य व आंतरिक रूप से हम पर हावी हो सके।"

उग्रवादियों के विरुद्ध प्रो-एक्टिव एवं सतत् अभियान चलाना आवश्यक है। और इसके लिए सभी उपाय किए जाने वाहिए, साथ ही विकास व सुशासन मुद्दों पर विशेषकर निचले स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः आज हमें ऐसी कोशिस करनी चाहिए कि जिससे भारत के सर्वांगिण विकास हो सके और विश्वपटल पर भारत का नाम स्थापित हो।"

नक्सलवादियों को हथियार उपलब्ध कराने का काम कर सकता है चीन भारत में नक्सलियों को नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान होकर हथियार उपलब्ध करवा सकता है इसलिए भारत में परिस्थितियां सामान्य नहीं है। आज नक्सलवाद अपने को शोषण वर्ग व्यवस्था के विरूद्ध उग्र वैचारिक आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह अपने कृत्यों से अन्ततः समाज को विभक्त करता है।

भारत में नक्सलियों द्वारा किए गये प्रमुख हिंसात्मक घटनाएं

भारत में नक्सलवाद घोर हिंसक कार्यवाहियो का पर्याय बन चुका है और कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती देते नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार देश के 13 राज्यों के 170 से भी ज्यादा जिलों में नक्सलवाद का असर है नक्सलवाद के चलते देश में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके है। दश की सबसे बड़ी नक्सली घटना माओवादी बिहार के जहानावाद में स्थानीय प्रशासन को कब्जा में लेकर जेल में बंद 389 कैदियों को छुड़ा ले गये।

2007: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा नक्सलियों ने 56 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उत्तार दिया था।

2008: ओड़िसा के नयागढ़ में नक्सलियों ने 14 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी।

2009: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 सी०आर०पी०एफ० जवान की मौत हो गई।

नक्सलवाद रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए गये प्रमुख अभियान-

एटीपेलवस अभियान यह अभियान 1971 में भारतीय सेना व राज्यों के पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया जिमें भारी संख्या में नक्सली मारे गये।

ग्रीन हंटन अभियान यह अभियान 2009 में छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में चलाया गया।"

प्रहार-2017 में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अभियान था।

नक्सलियों को सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख योजना

नक्सली हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया।

नक्सलरोधी योजना के तहत सरकार ने विकास कार्यों हेतु 7300 करोड़ रूपये का पैकेज आवंटित किया है। गृह मंत्रालय ने देश को नक्सली हिंसा से मुक्त कराने के लिए "नई पहल नाम की एक योजना लागू की है जिसके तीन प्रमुख अंग है-

i). विशेष अध्ययन
ii). सशस्त्र बलों की तैनाती
iii). पहल।

इस योजना के तहत सभी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण कर लिया गया है। नई पहल के तहत प्रथम चरण में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ के ट्राईजंक्शन पर स्थित महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले को चुना गया है।"

भारत सरकार तथा राज्य सरकारें नक्सलवादी इलाकों में योजनाओं को बहुत अधिक बढाया दे रहे है। सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार पिछड़े व प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात में राशि प्रदान कर रहा है।

नक्सली समस्या के अध्ययन हेतु खुफिया जाँच एजेन्सियों का भी सहारा लिया जा रहा

भारत सरकार हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर उनके पुर्नवास तथा ईनाम देने की नीति शुरू की है तथा तथा राज्य सरकारों से ऐसी ही नीतियों जारी करने के लिए कहा है। जो नक्सली हथियार डालेगे उनको तात्कालिक तौर पर 15 लाख रूपये ईनाम तथा लगभग 3 लाख तक के लिए व्यवसायिक प्रशिण के दौरान 3000 रूपये मासिक वेतन की बात की थी।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2014 में नक्सलवादियों की हिंसा या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिद्धान्त को समाप्त करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य प्रारंभ किए तथा मनोवैज्ञानिकदबाय भी बनाया। साथ ही इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल टावरों की स्थापना कौशल विकास शिक्षा सुविधाओं संबन्धित पहले शामिल हैं। पुलिस आधुनीकरण योजना 2017-20 के तहत- सुरक्षा संबन्धित व्यय योजना शुद्ध विशेष केंद्रीय सहायता शुद्ध 250 सुद्दढ़ पुलिस स्टेशनों निर्माण सहित विशेष आधारभूत संरचना योजना व आदि उपयोजनाएँ चलाई जा रही है।

माओवाद व नक्सलवाद से निपटने के लिए गष्ट मंत्रालय की अल्पकालिक व दीर्घकालिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करने की एक रणनीति समाधान है इसमें समाविष्ट है-

A-Smart Leadership (कुशल नेतृत्व)
1-Agressive strategy (अक्रामक रणनीति)
M-Motivation and Training (प्रोत्साहन और प्रशिक्षण)
A-Actionable Intelligence (कार्यवाही योग्य आसूचना)
क-वैश बोर्ड आधारित प्रमुख प्रर्दशन संकेतक Key perfemance Indicators; K) और प्रमुख परिणाम क्षेत्र (Key Result Area: KRA)
H-Harnessing Technology (प्रौद्योगिकी का दोहन)
A-Action plan for each theatre (प्रत्येक मोर्चे पर कार्य योजना)
N-No access to financing (वित्तपोषण तक पहुँच रोकना)

साथ ही ग्रामीण कौशल योजना के तहत 'रोशनी' एक विशेष पहल है जिसके अन्तर्गत निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और नियोजन की कल्पना की है। ब्लैक पैंथर फोर्स का गठन जो छत्तीसगढ़ में एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल है। इसके अलावा बस्तरिया बटालियिन एक नवगठित सीआरपीएफ बटालियन है जो छत्तीसगढ़ के 4 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलो से है जिसमे जनजातीय युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व (33 प्रतिशत) प्रदान किया है। यह अर्द्धसैनिक बलों की प्रथम संयुक्त बटालियन है।"

नक्सलवाद को समाप्त करने के सकारात्मक कदम तथा सुझाव विशेषज्ञों की राय में नक्सलवादियों से निपटने के लिए तीन स्तरीय रणनीति बनानी होगी। एक तो, सुरक्षा को चाक-चौबन्द करना और हर तरह की हिंसा की प्रतिकार की तैयारी इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं और कार्यक्रमो का प्रभावी क्रियान्वयन और तीसरे सभी नक्सल समूहों से संवाद के क्रम में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं सहयोग होने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त तीनों रणनीतियों के आलावा सरकार को चाहिए कि नक्सलियों को समाज की प्रमुख धारा में लाने का प्रयास किया जाए। भूमि सुधार व जंगल कानून लागू किया जाए। प्राकतिक संसाधनों पर स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें तथा राजनीतिक दलों को अपने निजी स्वार्थ आधारित राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समस्या को एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रभावित राज्यों की सरकारों द्वारा नक्सली गुटों के साथ शाति वार्ता करनी चाहिए।

संदर्भ-सूची

1. पाण्डेय सतीश चंद्र, एवं धीरेंद्र, द्विवेदी भारतीय सुरक्षा चुनौतियों एवं प्रतिक्रियाएँ, अध् ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2012, प५०-15-16
2. पलसानिया एम.ए.ए नक्सलवादः आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती,
3. योजना, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, मार्च 2006
4. राजकिशोर वनवासियों का संघर्ष, बाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 1995 पाठ 10-11,
5. यादव मुन्ना लालः भारत की शांति सुरक्षाः नवीन आयाम व चुनौतियों, प्रत्यूष पब्लिकेशन, दिल्ली, 2016, 0-262-263
6. श्रीवास्तव एवं मनोज, नक्सलवादः कारण, समस्या एवं समाधान, दया पब्लिशिंग हाउस, 2011
7. कुमार सतीश, कुमार बजरंग 21वी सदी भारत की सुरक्षा की चुनौतियां, मोहित पब्लीकेशन दिल्ली, 2016 पष्ठ 262-263
8. नय्यर वी०के० इण्डियाज सिक्यूरिटी पॉलिसी, परस्पेक्टिव्स एण्ड प्रोब्लम्स, सुमित इण्टरप्राईजेज, नई दिल्ली. 2014 पष्ठ 112, 113
9. मेनन वी० के० हू आर द नक्सल्स 2 ए ब्रेट टू इण्डियन डेमोकेसी, मुरारीलाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली 2011,
10. मिश्र विनोद मोहन, श्रीवास्तव डॉ०, अभय कुमार, नक्सलवादः भारतीय परिप्रेक्ष्य में।
11. सक्सेना, विवेक, राजेश सुशीलः नक्सली आतंकवाद, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016
12. भारत सरकार
13. सिंह, प्रकाशः नक्सलवादः दष्टिकोण और यथार्थ, चितन सष्जन, वर्ष-8 अंक-1, पष्० 32.33
14. दीवान ए०के० हूँ आर द नक्सलाइट, प्रधान जनरल, वाल्यूम-3 मार्च 2007
15. सिंह, प्रकाशः दी नक्सलाइट मुवमेंट इन इण्डिया, रूपा एण्ड कम्पनी नई दिल्ली, 2010 16. अग्रवाल पी०के० नक्सलिज्मः कॉजेज एण्ड केयर, मानस पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।।